BSNL EMPLOYEES UNION

Recognised Union in BSNL
(Registered Under Indian Trade Union Act 1926. Regn.No.4896)
CHQ:Dada Ghosh Bhawan, Opp. Shadipur Bus Depot., New Delhi – 110008
Email: bsnleuchq@gmail.com, website: bsnleuchq.com

P. Abhimanyu
General Secretary

Phone: (O) 011-25705385
Fax : 011- 25894862

बीएसएनएलईयू/102 (सर्कुलर सं.09) **16 जनवरी, 2018**

सेवा में,

सभी सर्किल सचिव,
केंद्रीय कार्यालय पदाधिकारी
और जिला सचिव

साथियो,

सहायक टावर कंपनी का गठन एक 'दिन दहाड़े डाका है"

तमाम नॉन–एक्जीक्यूटिवों और एक्जीक्यूटिवों ने सहायक टावर कंपनी के गठन का विरोध करते हुए गंभीर संघर्ष चलाए हैं। किंतु कर्मचारियों के भारी विरोध की अनदेखी करते हुए सरकार बीएसएनएल को टुकड़ों में तोड़ने के अपने ऐजेंडा पर आगे बढ़ रही है। जब डॉट ने सहायक टावर कंपनी के गठन के लिए कैबिनेट नोट भेजा तो तमाम नॉन–एक्जीक्यूटिवों और एक्जीक्यूटिवों ने इसका जोरदार विरोध किया और 15.12.2016 को एक दिन की व्यापक हड़ताल पर गए। इस प्रतिरोध की अनदेखी करते हुए सरकार ने 12.09.2017 को सहायक टावर कंपनी के गठन का फैसला लिया।

बीएसएनएलईयू का पक्का विचार है कि सहायक टावर कंपनी के गठन से बीएसएनएल डूब जाएगा। विगत समय में सरकार ने बीएसएनएल में विनिवेश शुरू करने की कई कोशिशें की हैं ताकि उसका निजीकरण किया जा सके। किंतु बीएसएनएल कर्मचारियो ने उन सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया। इसलिए सरकार ने एक और कोशिश के रूप में सहायक टावर कंपनी के गठन का सहारा लिया है ताकि बीएसएनएल को खत्म किया जा सके। सहायक टावर कंपनी गठित करने के पीछे मकसद बीएसएनएल को उसकी 70,000 मोबाइल टावरों से उसे वंचित करना है। आज की स्थिति में ये टावरें बीएसएनएल की जीवन रेखा हैं। अगर इन्हें छीन लिया गया तो बीएसएनएल का खात्मा निश्चित है।

बीएसएनएल प्रबंधन, खास तौर से सीएमडी बीएसएनएल यूनियनों और ऐसोसिएशनों को समझाने की भरसक कोशिश कर रहें हैं कि सहायक टावर कंपनी का गठन ही बीएसएनएल को घाटे से बाहर लाने का रास्ता है। इसके अलावा सीएमडी बीएसएनएल ने यूनियनों और ऐसोसिएशनों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि सहायक टावर कंपनी का प्रबंधन बीएसएनएल के नियंत्रण में होगा। किंतु ये सभी तर्क झूठे और भ्रामक साबित हुए हैं।

21.12.2017 को सरकार ने एक आइएएस अधिकारी, श्री अमित यादव जो डॉट में संयुक्त सचिव (एडमिन) हैं, को सहायक टावर कंपनी का चेयरमैन और मैनेजिंग डाइरेक्टर (सीएमडी) नियुक्त किया है। एक आइएएस अधिकारी की सहायक टावर कंपनी के सीएमडी के रूप में नियुक्ति स्पष्ट रूप से साबित करती है कि सहायक टावर कंपनी का प्रबंधन बीएसएनएल प्रबंधन के तहत नहीं होगा। यह नोट करना हास्यास्पद है कि सीएमडी बीएसएनएल और बीएसएनएल के दूसरे सक्रिय निदेशक नव गठित सहायक टावर कंपनी के बोर्ड निदेशक हैं। यह नोट करना दुःखद है कि देश की एक सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी बीएसएनएल का सीएमडी सहायक टावर कंपनी के सीएमडी की चेयरमैनशिप के नीचे रहेगा। इसके अलावा एक आईएएस अधिकारी की सहायक टावर कंपनी के सीएमडी के रूप में नियुक्ति यह स्पष्ट करती है कि बीएसएनएल की तमाम मोबाइल टावरें सीधे सरकार के नियंत्रण में होंगी। इसलिए कहने की जरूरत नहीं कि सहायक टावर कंपनी का गठन 'दिन दहाड़े डकैती' के अलावा और कुछ नहीं है।

तीसरा वेतन संशोधन–सरकार अपने कदम पीछे घिसट रही है

बीएसएनएलइयू, एसएनइए, एफएनटीओ, एआइजीइटीए और बीएसएनएल एमएस ने फौरन तीसरे वेतन संशोधन और पेंशन संशोधन की मांग करते हुए 27.07.2017 को एक दिवसीय बहुत ही सफल हड़ताल का आयोजन किया। इस हड़ताल के बाद "ऑल यूनियंस एंड ऐसोसिएशंस" द्वारा 12 और 13 दिसंबर, 2017 को एक दो दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया। ये दोनों हड़तालें बहुत सफल रहीं। किंतु, सरकार द्वारा अभी तक बीएसएनएल यूनियनों और ऐसोसिएशनों की इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया है कि बीएसएनएल को तीसरी वेतन समिति के वहनीयता के अनुच्छेद से छूट दी जाए। इस बीच नॉन–एक्जीक्यूटिवों के वेतन संशोधन के लिए डीपीई गाइडलाइनें 24.11.2017 को जारी कर दी गई हैं जिसमें वहनीयता से संबंधित कोई अनुच्छेद नहीं है। नॉन–एक्जीक्यूटिवों के लिए संयुक्त वेतन वार्ता कमेटी के गठन को अभी तक डॉट ने क्लीयर नहीं किया है।

बीएसएनएल कर्मचारियों पर जो एक और हमला किया जा रहा है वह बीएसएनएल को डॉट की, सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने की गाइडलाइनें हैं। किन्ही भी परिस्थितियों में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह बड़ी संख्या में बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए एक बड़ा धक्का होगा जो सेवानिवृत्ति के नजदीक हैं। इसके अलावा 2 लाख बीएसएनएल पेंशन धारक 01.01.2017 से अपनी पेंशन के बारे में बहुत ही चिंतित है जो भारत सरकार की पेंशन योजना में कवर होते हैं। जब सरकार ने भारत सरकार की पेंशन में कवर होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को पहले ही संशोधित कर दिया है तो बीएसएनएल पेंशनर्स को पेंशन संशोधन से वंचित करने का एकदम कोई औचित्य नहीं है। सीधे भर्ती बीएसएनएल कर्मचारी कंपनी का भविष्य हैं। उनके सेवानिवृत्ति लाभों के मुद्दे को हल न करने से उनका भविष्य बर्बाद होगा।

बीएसएनएल की ऑल यूनियंस एंड ऐसोसिएशंस की 08.01.2018 को नई दिल्ली में हुई मीटिंग में सहायक टावर कंपनी के गठन को वापस लेने, तीसरे वेतन संशोधन के हल के लिए लगातार संघर्ष चलाने का बीएसएनएल कर्मचारियों का आह्वान किया गया है। संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए बीएसएनएलईयू, एनएफटीई, एसएनइए और एआइबीएसएनएलइए के जनरल सेक्रेटरीज के साथ एक संचालन

समिति का गठन किया गया है। मीटिंग में सहायक टावर कंपनी के गठन को शिकस्त देने के लिए कानूनी सलाह लेने का भी फैसला लिया गया है। बीएसएनएल की ऑल यूनियंस एंड ऐसोसिएशंस द्वारा तय किए आंदोलन कार्यक्रम और मांगपत्र निम्नलिखित हैं :

संघर्ष का कार्यक्रम

1. 30.01.2018 से 5 दिन का पूरा दिन सत्याग्रह। सत्याग्रह 30.01.2018 को बीएसएनएल की ऑल यूनियंस एंड ऐसोसिएशंस के नेताओं द्वारा गांधीजी की समाधि पर श्रृद्धांजलि अर्पित करके आरंभ किया जाएगा।
2. 30.01.2018 से 'अनिश्चित कालीन वर्क टू रूल'।
3. 23.02.2018 को सामूहिक 'संसद मार्च'

मांगपत्र

1. निम्नलिखित को हल करो:
   क) 01.01.2017 से 15 प्रतिशत फिटमेंट के साथ तीसरा वेतन संशोधन।
   ख) पेंशन संशोधन को हल करो।
   ग) दूसरे पीआरसी के बकाया मुद्दों को हल करो
2. सहायक टावर कंपनी के गठन को रद्द करो।
3. सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष नहीं की जाए और कोई वीआरएस नहीं।

बीएसएनएलईयू की सभी सर्किल और जिला यूनियनों से संघर्षों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए फौरन कार्रवाई में कूदने का अनुरोध है। संघर्षों को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए उन्हें बीएसएनएल की ऑल यूनियंस एंड ऐसोसिएशंस के दूसरे घटको के साथ समन्वय स्थापित करने भी पहल करनी चाहिए।

सीईसी मीटिंग अगरतला में

नई दिल्ली में 07 और 08 नवंबर 2017 को हुई सीईसी मीटिंग के निर्णय के अनुसार अगली सीईसी मीटिंग अगरतला, एनई–1 सर्किल में होगी। नई दिल्ली मीटिंग ने यह भी तय किया है कि अगरतला मीटिंग एक विशेष सत्र होगी जिसमें पिछली चेन्नई अखिल भारतीय कान्फ्रेंस के फैसलों को लागू करने की मध्यावधि समीक्षा और उसके बाद हुई सीईसी मीटिंगों के फैसलों को लागू करने की भी समीक्षा की जाएगी। अखिल भारतीय केंद्र ने तय किया है कि अगली सीईसी मीटिंग की तिथियां 03, 04, और 05 अप्रैल 2018 होंगी। फैसलों को वेबसाइट अपडेटिंग और व्हाट्सअप मेसेज के जरिए पहले ही सीईसी सदस्यों को सूचित किया जा चुका है। सीईसी मीटिंग के लिए शीघ्र ही नोटिस जारी कर दिया जाएगा। सभी सीईसी सदस्यों से बिना चूक किए मीटिंग में भाग लेने का अनुरोध है। यह भी नोट करना चाहिए कि सीईसी मीटिंग में किसी भी विजिटर को इजाजत नहीं दी जाएगी।

सीएचक्यू कोटा के जिलाबार ब्रेक–अप आंकड़े – सर्किल सकिवों की निश्क्रियता पर भारी अफसोस

इआरपी लागू किए जाने के बाद अखिल भारतीय यूनियन चंदे का कोटा एनइएफटी के माध्यम से सीएचक्यू को भेजा जाता है। एनइएफटी के माध्यम से सीएचक्यू को कोटा भेजते समय सर्किल प्रशासन सीएचक्यू कोटा के जिलाबार ब्रेक–अप आंकड़ों के बारे में सीएचक्यू को मासिक विवरण नहीं भेज रहे हैं। सीएचक्यू ने इस संबंध में कारपोरेट ऑफिस को पहले ही पत्र लिखा है। इसके बाद कारपोरेट ऑफिस ने सीएचक्यू को जिलाबार ब्रेक–अप आंकड़ों के साथ सीएचक्यू को विवरण भेजने का निर्देश देते हुए पहले ही सभी सीजीएम्ज को पत्र लिखा है। लेकिन, मध्य प्रदेश सर्किल प्रशासन को छोड़कर कोई भी सीएचक्यू को ऐसा विवरण नहीं भेज रहा है। इस मुद्दे पर नई दिल्ली सीईसी मीटिंग में चर्चा हुई थी। यह तय किया गया था कि सर्किल सचिवों को वर्ष 2016 और 2017 के लिए सीएचक्यू को जिलाबार ब्रेक–अप आंकड़े प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें सीएचक्यू को भेजना चाहिए। इसके अलावा यह भी तय किया गया था कि सर्किल यूनियानों को जिलाबार ब्रेक–अप आंकड़ों के साथ सीएचक्यू को मासिक विवरण भेजने के लिए अपने अपने सीजीएम्ज के साथ इस मुद्दे को गंभीरता से उठाना चाहिए।

यह नोट करना बहुत ही चिंताजनक है कि इस मुद्दे पर किसी भी सर्किल यूनियन ने कार्रवाई नहीं की है। सर्किल सचिवों को सूचना हेतु मध्य प्रदेश सर्किल प्रशासन द्वारा सीएचक्यू को भेजे गए मासिक विवरण की एक प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है। सभी सर्किल सचिवों से अनुरोध है कि वे इस मुद्दे को अपने अपने सीजीएम्ज के साथ उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि सीएचक्यू को हर माह जिलाबार ब्रेक–अप आंकड़ों के साथ मासिक विवरण भेजा जाए। सर्किल सचिवों से यह भी अनुरोध है कि वे वर्ष 2016 और 2017 के लिए कोटा के जिलाबार ब्रेक–अप आंकड़े प्राप्त करें और फौरन सीएचक्यू को भेजें।

सधन्यवाद,
आपका

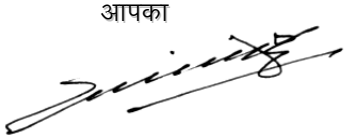

(पी अभिमन्यु)
जनरल सेक्रेट्री